अब आम लोग भी लगा सकेंगे सीएनजी स्टेशन, गेल ने खोला रास्ता

एमडीए और नगर निगम के साथ आम जनता को भी मिली जगह

जनवरी-फरवरी 2027 में ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा

● राजीव कुमार, जनवाणी, मेरठ

अगर आपके पास जमीन है और सीएनजी स्टेशन का कारोबार करना चाहते हैं तो मेरठ में जल्द आपके लिए भी मौका आने वाला है। अब सीएनजी स्टेशन लगाने की दौड़ में सिर्फ सरकारी विभाग, एमडीए या नगर निगम ही नहीं रहेंगे, बल्कि आम लोग भी आवेदन कर सकेंगे। गेल गैस लिमिटेड ने निजी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी की है। जनवरी और फरवरी 2027 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा।

मेरठ में सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ स्टेशन की जरूरत भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए गेल गैस शहर के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास सीएनजी नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नए स्टेशन खुलने से कंपनी को भी नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी और वाहन चालकों को सीएनजी भराने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। बता दें कि गेल गैस ने नगर निगम को 29 अगस्त को भेजे पत्र में शहर के प्रमुख मार्गों पर निगम की जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। निगम चाहे तो जमीन सीएनजी स्टेशन के लिए लीज पर दे सकता है या खुद स्टेशन चलाकर नियमित मासिक आय हासिल कर सकता है। इसी के साथ निजी क्षेत्र के लोगों के लिए भी स्टेशन लगाने का रास्ता खुल रहा है। कंपनी का मानना है कि अधिक स्टेशन होने से सीएनजी की उपलब्धता बेहतर होगी और मेरठ में गैस आधारित ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ सीएनजी वाहनों को भी इसका लाभ मिलेगा। गेल ने नगर निगम को भेजे पत्र में बताया कि एक सीएनजी स्टेशन से राज्य सरकार को हर साल करीब चार से पांच करोड़ रुपये तक राजस्व मिलने का अनुमान है। इसमें 14 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 12.5 प्रतिशत वैट शामिल है। इसके अलावा जमीन उपलब्ध कराने पर एमडीए को भी मासिक राजस्व मिलने की बात कही गई है।

आम लोग भी कर सकेंगे आवेदनः विनय कुमार

गेल गैस के महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप की तरह अब सीएनजी स्टेशन के क्षेत्र में भी निजी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। इच्छुक लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीएनजी स्टेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए प्रमुख मार्गों पर उपयुक्त जमीन उपलब्ध होना जरूरी होगा। नगर निगम, एमडीए समेत सरकारी संस्थानों की जमीन भी सीएनजी स्टेशन के लिए विकल्प बन सकती है। इससे लोगों को कारोबार का अवसर मिलने के साथ शहर में सीएनजी की उपलब्धता बढ़ेगी और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी।

नेटवर्क बढ़ा तो वाहन चालकों को मिलेगी राहत

शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्टेशन बढ़ने से वाहन चालकों को सीएनजी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गेल पहले से मेरठ के शहरी क्षेत्रों में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ सीएनजी स्टेशनों को गैस की आपूर्ति कर रही है। पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार भी लगातार किया जा रहा है। गेल गैस का मेरठ कार्यालय जागृति विहार में एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के सामने गढ़ रोड पर है। स्थानीय कार्यालय के फोन नंबर 0121-2603559 और 0121-2603550 हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय और इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

तेल आपूर्ति पर अब बाब अल-मंदेब ने बढ़ाई चिंता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

होर्मुज जलमार्ग से बाधित तेल आपूर्ति की समस्या जैसे-तैसे संभल ही पाई थी कि अब बाब अल-मंदेब का संकट गहराता दिख रहा है। हूती हमलों से इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने के बाद भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है और तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों से संपर्क तेज कर दिया है। घरेलू स्थिति पर अंतर-मंत्रालयी समिति लगातार नजर रख रही है। इंडियन आयल कार्पोरेशन, ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियां समिति को रोजाना रिपोर्ट दे रही हैं। विदेश मंत्रालय ने हालात पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 सितंबर को दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भेंट में यह मुद्दा उठाया। भारत बाब अल-मंदेब मार्ग से सऊदी तेल भी ला रहा था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, भारत सऊदी अरब पर हुए हमलों की निंदा करता है। ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करते हैं और बाब अल-मंदेब से आने-जाने की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाते हैं। कहा कि उस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति फिलहाल जारी है और शांति बहाली की उम्मीद है। भारत इसलिए चिंतित है, क्योंकि लाल सागर और बाब अल-मंदेब उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए संवेदनशील रास्ते हैं। पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे तेल, एलपीजी और कुछ रिफाइंड उत्पादों का बड़ा हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से गुजरता है। बाब अल-मंदेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और अफ्रीका महाद्वीप (जिबूती और इरिट्रिया) के बीच एक संकरा जलमार्ग है।

- **भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई और तेल आपूर्ति करने वाले देशों से संपर्क किया तेज**
- **विदेश मंत्रालय ने हालात पर चिंता जताई, कहा,उस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति फिलहाल जारी**

एक स्रोत पर निर्भरता नहीं

हूती हमले, सऊदी सुविधाओं पर हमले या जहाजों का लंबा चक्कर तीन तरह से असर डाल सकता है- खेप देर से पहुंचना, बीमा व भाड़ा बढ़ना व तेल की कीमतें चढ़ना। भारत पर इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। रूस, खाड़ी के वैकल्पिक बंदरगाह, अफ्रीका और अन्य देशों से खरीद पहले से चल रही है। असली खतरा तब बढ़ेगा जब लाल सागर संग होर्मुज जैसे दूसरे मार्ग भी लंबे समय तक ठप रहें।

कच्चा तेल प्रति बैरल 100 डालर के पार

लाल सागर और बाब अल-मंदेब पर बढ़े तनाव के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रूड फिर से 100 डालर प्रति बैरल को पार कर गिया है। मंगलवार को ब्रेंट करीब 106 से 107 डालर प्रति बैरल के आसपास रहा। सोमवार को दोनों मानक करीब एक प्रतिशत चढ़े थे और सत्र के दौरान ब्रेंट 109 डालर के करीब भी दिख गया था। बढ़ोतरी की बड़ी वजह सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का बंद रहना है, जिसके जरिये होर्मुज को छोड़कर तेल यनबु और लाल सागर की ओर भेजा जाता था। हूती हमलों और लाल सागर मार्ग के जोखिम ने उसी वैकल्पिक रास्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार में अनुमान है कि पाइपलाइन अगर हफ्तों बंद रही तो ब्रेंट 120 से 130 डालर तक जा सकता है।

Dainik Jagran, Delhi, 16/09/2026
Page No: 19, Size: 21.51cm × 41.09cm

तेल आपूर्ति पर होर्मुज के बाद बाब अल-मंदेब ने बढ़ाई चिंता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : होर्मुज जलमार्ग से बाधित तेल आपूर्ति की समस्या जैसे-तैसे संभल ही पाई थी कि अब बाब अल-मंदेब का संकट गहराता दिख रहा है। हूती हमलों से इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने के बाद भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है और तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों से संपर्क तेज कर दिया है। घरेलू स्थिति पर अंतर-मंत्रालयी समिति लगातार नजर रख रही है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन, ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियां समिति को रोजाना रिपोर्ट दे रही हैं। विदेश मंत्रालय ने हालात पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था। भारत बाब अल-मंदेब मार्ग से सऊदी तेल भी ला रहा था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत सऊदी अरब की संप्रभु जमीन पर हुए हमलों की निंदा करता है, खासकर नागरिक ढांचे और आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाने वाले हमलों की। ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करते हैं और बाब अल-मंदेब से आने-जाने की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाते हैं। जायसवाल ने इन्हें

रणधीर जायसवाल ●

भारत के लिए अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति फिलहाल जारी है और शांति बहाली की उम्मीद है। भारत इसलिए चिंतित है, क्योंकि लाल सागर और बाब अल-मंदेब उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए संवेदनशील रास्ते हैं। पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे तेल, एलपीजी और कुछ रिफाइंड उत्पादों का बड़ा हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से गुजरता है। बाब अल-मंदेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और अफ्रीका महाद्वीप (जिबूती और इरिट्रिया) के बीच एक संकरा जलमार्ग है। भारत एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। रूस, खाड़ी के वैकल्पिक बंदरगाह, अफ्रीका और अन्य देशों से खरीद पहले से चल रही है।

कच्चा तेल 100 डालर के पार : लाल सागर और बाब अल-मंदेब पर बढ़े तनाव के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रूड फिर से 100 डालर प्रति बैरल को पार कर गया है। मंगलवार को ब्रेंट करीब 106 से 107 डालर प्रति बैरल के आसपास रहा।

Business Line, Delhi, 16/09/2026

Page No: 3, Size: 44.87cm × 12.78cm

Closing of East-West pipeline makes crude oil more expensive for Indian refiners

Rishi Ranjan Kala
New Delhi

The shutting down of the East-West crude oil pipeline by Saudi Arabia, accounting for roughly 4 per cent of global supply, is likely to make barrels more expensive.

The closure of the 1,200-km-long pipeline, which transports crude oil from Abqaiq to the Yanbu port on the Red Sea, is not expected to lead to major supply disruptions.

However, the disruption of roughly 4 million barrels per day (mb/d) of crude oil supply is further fuelling uncertainty that is reflecting in rising prices. By 1830 hours on Tuesday, Brent was trading at $106.1 per barrel, WTI at $102.3 and Murban at $120.8 a barrel.

Sources said that high crude oil prices coupled with a record weak Indian rupee against the US dollar will further inflate the crude import bill. For instance, India's crude oil import bill is already higher by more than 56 per cent Y-o-Y at roughly $63.4 billion during April-July in FY27.

Kpler pointed out that closure of the Saudi East–West Pipeline further reduces routing flexibility for Indian refiners at a time when several key oil transit routes are already under pressure.

India will likely lean even more on diversification across Russia, the US, West Africa, Latin America and other non-Middle East sources to reduce exposure to any single corridor.

HIGHER IMPORT BILL

Sumit Ritolia, Kpler's Lead Research Analyst for Refining & Modeling, told *businessline*, "The bigger risk for

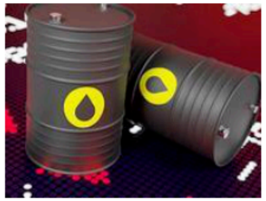

India is not only physical availability of crude, but the rising landed cost. Higher crude prices, freight, insurance and longer voyages all increase the delivered cost of barrels."

For India, this means a higher oil import bill, more pressure on the current account deficit (CAD) and the Rupee, and a greater inflationary risk if elevated energy costs persist, he anticipated.

India's CAD has risen to $11.2 billion during April-July this fiscal year against $6.6 billion during the same period in FY26. A $10 per barrel increase in crude prices adds about $13-14 billion to the import bill.

High energy prices have also started reflecting in rising inflation. Dharmakirti Joshi, Chief Economist at Crisil, said the Consumer Price Index (CPI)-based inflation resurged to 4.8 per cent, reflecting a broadening of price pressures across both food and non-food categories.

Joshi emphasised that external risks are becoming more pronounced. Inventory depletion and persistent geopolitical tensions in West Asia have prompted Crisil Intelligence to revise its Brent crude forecast for FY27 upward to $88-93 per barrel, implying a 25-32 per cent on-year increase.

Pinky Yadav, Commodity Fundamental Analyst at Choice Broking, said that MCX crude oil prices rose around 2 per cent as escalating geopolitical risks and supply disruptions fuelled market volatility. Continued shutdown of East-West pipeline following drone attacks, coupled with the abrupt postponement of regional diplomatic talks strained energy security. Tanker transits through the critical Strait of Hormuz plunged to single digits.

Heightened friction around the SoH, including reports of an exploding super tanker, further rattled investors, despite US President Donald Trump's claims of an agreement between Moscow and Kyiv to cease strikes on energy infrastructure, Yadav added.

Business Line, Delhi, 16/09/2026
Page No: 5, Size: 34.63cm × 34.53cm

Decoding BRICS' energy intent

It provides a vital diplomatic cover for India to keep its oil import options open without having to take sides

CAPITAL IDEAS.

RICHA MISHRA

ENERGY SOVEREIGNTY. India must be diplomatically nimble in sourcing oil /ISTOCKPHOTO

"We acknowledge fossil fuels will still play an important role in the world's energy mix, particularly for emerging markets and developing economies, and we recognize the need to promote just, orderly, equitable and inclusive energy transitions and reduce GHG emissions in line with our climate goals and observing SDG7, and the principles of technological neutrality and common but differentiated responsibilities and respective capabilities taking into account national circumstances, needs and priorities," reads BRICS New Delhi Declaration of September 12, 2026.

By validating the ongoing importance of fossil fuels, the declaration provides the energy sector with a critical defence: it rejects an aggressive phase-out in favour of a realistic, managed transition, which, some say, is good for India, Russia and Saudi Arabia.

But this should not be seen as a free pass to energy-import reliant nations like India. What BRICS membership actually does is provide vital diplomatic leverage: it keeps India and Iran at the negotiating table, safeguarding India's access to the strategic Chabahar Port.

KEY POINTS

Energy security: Ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources, strengthening value chains. This is a priority after West Asia conflict.

Digital and Smart Grids: BRICS pushed AI, data analytics for grid management.

Diversified mix: Declaration lists all sources as important — renewable energy, bioenergy, fossil fuels, nuclear energy, hydropower, hydrogen, low carbon technologies, energy storage.

Critical Minerals Focus on reliable supply chains for lithium, cobalt, copper, but with sovereign rights of resource countries.

Local currencies: Finally, Energy Ministers called for use of local currencies in energy trade.

The declaration provides for Smart Grids & Storage Centre in India; Push for Global Biofuels Alliance; reliable and stable supply chains for minerals. India needs lithium for EVs, solar, semiconductors.

In the wake of ongoing West Asia conflicts and Red Sea disruptions, India wants to insulate its economy by sourcing crude oil from Russia, the Gulf, or the US without the threat of unilateral sanctions. The BRICS Energy Ministers' parallel push for local currency trade offers a vital financial shield.

Settling transactions in rupees, rubles, or dirhams reduces US dollar dependency, minimises exposure to secondary sanctions, and structurally protects India's foreign exchange reserves. RBI already has rupee settlement mechanism for Russian oil.

> **Settling transactions in rupees, rubles, or dirhams reduces US dollar** dependency, minimises exposure to secondary sanctions

With the West Asia conflict disrupting the Strait of Hormuz, the declaration's emphasis on "diverse sources" provides India with the diplomatic leverage to source oil from Russia, the US, the UAE, and Iraq. Whether this strategic framing explains why New Delhi persistently purchased discounted Russian crude despite heavy Western pressure remains a question only the Ministry of External Affairs can answer.

Protection of critical energy infrastructure, including cross-border infrastructure is a boostfor India as this means undersea cables, LNG terminals, proposed India-Middle East-Europe pipeline, and power grid connections with Nepal, Bhutan, Bangladesh could be in offing.

The declaration can even be seen as an endorsement of India's approach: keep coal and gas for baseload, add solar and wind rapidly, secure oil from cheapest source, and build storage.

THE CHALLENGES

However, there are challenges. BRICS is opposed to EU's carbon tax, but EU's CBAM has kicked in from January 1, 2026. Indian steel and aluminium will still pay at EU border from this year. India will need to take this up at WTO and build its own carbon credit system fast. Clearly, just a joint statement won't stop the tax. India ramped up Russian oil purchases — from 2 per cent to 35 per cent — because it was cheap ($20-30 discount), but that is now down to $3-5 a barrel.

India will get hurt if it gets too reliant on one supplier and US tightens secondary sanctions. Energy security implies diversification of supply sources, not substituting West Asian dependence with Russian dependence.

The Declaration talks about resilient supply chains, but India has no lithium, cobalt, nickel processing. India's Critical Mineral Mission needs to secure mines in Brazil, South Africa, Argentina, not just MOUs.

A critical question is, will Iran allow free and smooth access? On the face of it Iran is not blocking, but inviting transit right now. The greater risk is not Iran but US sanctions.

Hormuz right now is technically open but practically almost closed. Iran wants to resume oil sales to India to broaden its buyer pool beyond China and India is pushing Chabahar as an alternative to Hormuz, open to Arabian Sea.

Hormuz is not a BRICS waterway, it's Iranian and Omani sovereign waters. BRICS declaration says 'undisrupted flows' and 'protection of critical infrastructure' but that doesn't ensure free access to BRICS.

According to information available, the Iranian side met Indian Oil Ministry top brass on BRICS sidelines specifically to offer crude to India.

As a member of both BRICS and the US-led Quad, India must walk a diplomatic tightrope. Pushing too aggressively for de-dollarisation and Rupee-denominated oil trade risks a backlash from Washington, which could jeopardise critical Western technology transfers in strategic sectors like semiconductors and civil nuclear energy.

Ultimately, New Delhi will need to tread cautiously, ensuring its pursuit of strategic autonomy does not come at the cost of its vital partnerships with the West.

The Declaration gives India political cover, but execution is on India: build storage, fix Discoms, mine minerals, and diversify supply sources.

Free Press Journal, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 11, Size: 13.94cm × 27.68cm

India's crude basket hits $128.70, D-St trembles

FPJ News Service
MUMBAI

India's crude basket has rocketed to $128.70 /barrel, its highest since April, nearly doubling from $67.16 on July 2, but below $157.04 on March 23. The energy shock is becoming Dalal Street's key macro risk, threatening earnings, valuations, inflation and the RBI's policy trajectory.

MKT FAULTLINES DEEPEN

Kotak Institutional Equities said equities are fretting over elevated crude amid Hormuz blockade, escalating Middle East conflict, supply-disruption risks and shrinking global inventories. India imports more than 85% of its crude; estimates suggest every $10 increase adds $13-14 billion to the annual import bill and 30-50 basis points to retail inflation. Aviation faces the sharpest hit, with jet fuel accounting for roughly one-third to 40% of operating costs. Paints, tyres and petrochemicals face raw-material inflation, while logistics, cement and FMCG confront freight and packaging pressure. OMC margins risk compression if pump prices lag crude, whereas upstream producers benefit through stronger realisations. MOFSL expects limited immediate inflation transmission if domestic fuel prices remain buffered, but warns second-round effects through transport, chemicals, plastics, synthetic fibres, manufacturing and services could prove damaging. Smaller, leveraged companies are exposed to a prolonged oil spike.

RATE-HIKE

August CPI accelerated to an eight-month high of 4.82% from 4.45%, with rural inflation at 5.23%, urban inflation 4.31%, food inflation 5.66% and core inflation 4.16%, against 3.87% in July. SBI Research expects CPI to breach 6.5% before retreating below 6% in early 2027 and favours 25-bps hikes in October and December.

Free Press Journal, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 11, Size: 20.77cm × 19.53cm

Crude shock pummels equities, Nifty sinks to fresh 5-month low

FPJ News Service
MUMBAI

Domestic equities endured a sell-off on Tuesday as surging crude, a 5% US Treasury yield and geopolitical stress triggered risk-off positioning.

The Sensex slumped 777.94 points, or 1.04%, to 74,003.82, a three-month trough, while the Nifty shed 279.50 points, or 1.19%, to 23,118.60, its weakest close since April 6.

The Sensex opened firmer before late-morning liquidation overwhelmed bids, dragging it to an intraday low of 73,994.03, down 787.73 points, or 1.05%.

Banking, automobiles and oil and gas absorbed selling, while mid- and small-caps underperformed as market breadth deteriorated. Bharat Electronics plunged 6%, with InterGlobe Aviation, Titan,

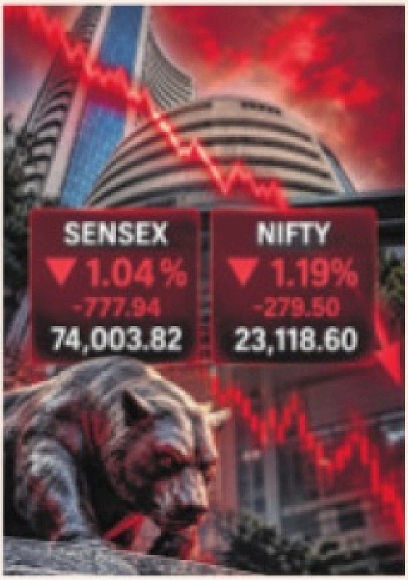

Bajaj Finserv, Adani Ports, Mahindra & Mahindra and State Bank of India among laggards. Technology emerged as the defensive pocket: HCL Tech surged 3.98%, Infosys 3.64%, Tech Mahindra 2.31% and TCS 2.18%, while HDFC Bank gained 1.27%.

Brent crude climbed 1.89% to $107.7 a barrel, intensifying inflation, earnings and margin anxieties. Geojit Investments' V K Vijayakumar flagged the US 10-year yield hitting the psychological 5% threshold and damage to Saudi Arabia's East-West oil pipeline following a Houthi attack.

Markets now confront the FOMC decision, with Vijayakumar expecting Kevin Warsh to favour a 25-basis-point increase despite President Trump opposing tightening. Persistent foreign outflows and restrictive global financial conditions threaten further multiple compression, although IPO buoyancy, value buying and clarity over HDFC Bank's next MD and CEO offer limited downside buffers.

Volatility could deepen unless energy costs retreat, yields soften and geopolitical strains ease, leaving bulls dependent on resilient earnings momentum.

Free Press Journal, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 13, Size: 7.22cm × 20.06cm

Crude surge could force fuel hikes

Sustained high crude prices could force India to raise retail fuel prices and push the Reserve Bank of India towards monetary tightening, Kotak Securities' Anindya Banerjee said.

With Brent around $106 a barrel, Banerjee warned that a sustained climb towards $120 could overwhelm buffers provided by oil marketing companies and government taxes, eventually transmitting costs to petrol and diesel consumers.

A weaker rupee compounds the pressure by making imported crude costlier.

With the currency beyond 95.80 per dollar, Banerjee sees 96 as an important threshold for RBI intervention.

He said persistent oil inflation and rupee depreciation could worsen India's inflation trajectory.

Financial Express, Delhi, 16/09/2026

Page No: 3, Size: 14.79cm × 22.12cm

WAR FALLOUT: NAPHTHA, LPG CONSUMPTION TAKES A HIT

CONSUMPTION OF NAPHTHA, a key feedstock for the petrochemical value chain comprising polymers-- to-plastics, synthetic textiles and other materials and rubber has contracted each month since December 2024, barring February this year . The rise in global crude prices, caused by supply disruptions from the war in West Asia, has led to lower capacity utilisation at naphtha crackers. The fall may partly stem from increased use of gas as petrochemical feedstock. Consumption of liquefied petroleum gas, which accounts for 13% of total petroleum products consumption, also contracted for six consecutive months through August due to price hikes following supply disruptions. However, consumption of transportation fuels remained resilient. **Compiled by Saikat Neogi**

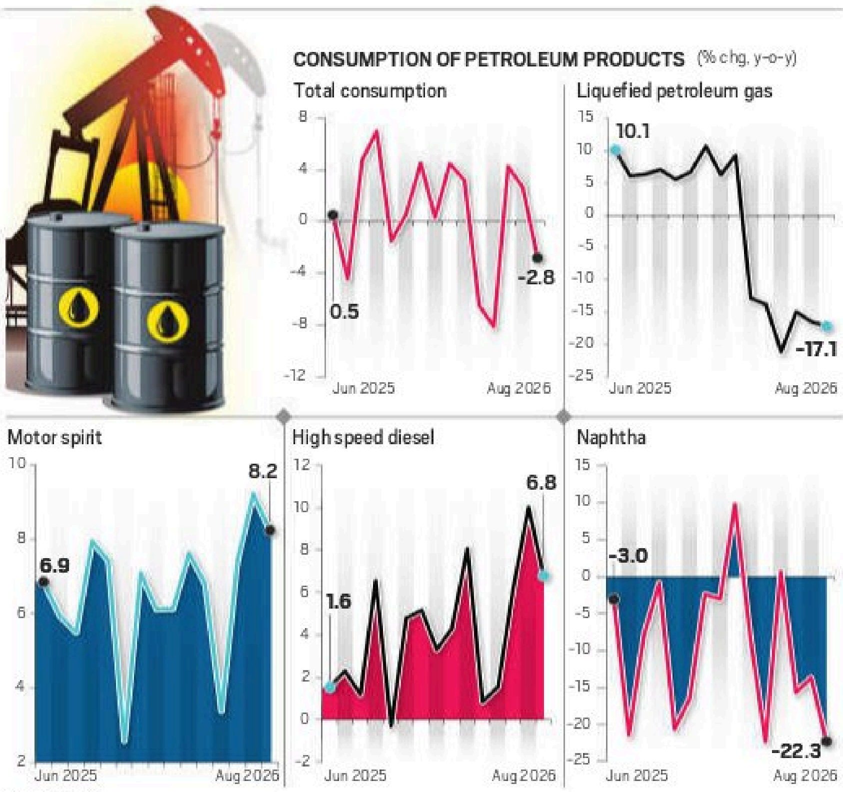

Source: CMIE

Free Press Journal, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 27, Size: 20.98cm × 24.87cm

Russia sanctions: US lawmaker seeks to name India among trading partners

PTI
WASHINGTON

Racing against time, US lawmakers submitted amendments to the Russia sanctions bill, with one seeking to name its top trading partners — including India — in the legislation, and another proposing to scrap the section imposing tariffs altogether.

The Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act, passed by the US Senate by an overwhelming 86-11 vote last month, seeks to impose sanctions not only on Russia's leadership and energy sector, but also on the "shadow fleet" of vessels that enable Moscow to evade sanctions on oil deliveries.

The US believes that Russia's crude oil trade is funding the war against Ukraine. The bill also seeks to authorise President Donald Trump to impose 100% tariffs on Russia's top oil trading partners, including China and India.

The bill passed by the US Senate on Aug 7 does not name Russia's trading partners, but mentions the five largest importers of oil and gas by volume. The bill must be passed by the House of Representatives before it is sent to the President for signature. The House has four working days left before it breaks into early recess ahead of the midterm elections on Nov 3.

Amendment seeks 100% duties on India and other Russian trading partners

The amendment moved by Democratic Congressman Steny Hoyer seeks to name China, India, Turkiye, Azerbaijan, Hungary, the Slovak Republic, the UAE, Singapore, Kazakhstan, and the Kyrgyz Republic as countries eligible for 100% duties.

Interestingly, Democratic Congressman Gregory Meeks, who is staunchly opposed to granting more tariff-levying powers to Trump, has moved an amendment to scrap the entire Section 113 that seeks to grant authority to the President to impose broad secondary tariffs on Russia's trading partners.The amendments to the Russia sanctions act were made public by the House Rules Committee on Monday.

Economic Times, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 14, Size: 15.21cm × 44.21cm

India's Natural Gas Imports Rise Despite Sharp Price Surge

Sanjeev Choudhary

New Delhi: India's natural gas imports continued to grow despite a sharp rise in prices this fiscal year. Demand got a boost from a subsidised fertiliser sector, growing CNG vehicle sales, limited supply of alternative fuels such as LPG and falling domestic gas production.

However, a recent surge in spot liquefied natural gas (LNG) prices to $25 per mmbtu may partly dent demand or push consumers towards alternative fuels, said industry executives.

With Gulf gas supplies disrupted due to the Iran war, India is currently sourcing about 35-40% of its imports from the spot market. Asian spot benchmark JKM averaged $19 per mmbtu in the April-August period, up from $12 in the same period last year.

Spot LNG has been pricier than those procured under long-term contracts where rates are linked to crude oil or the US gas benchmark and have risen far less. At an April-August Brent average of $90 per barrel, LNG could have cost $11-12/mmbtu, while the US gas benchmark has remained unchanged from last year.

Some local suppliers have been blending volumes from expensive spots and cheaper long-term contracts to keep LNG rates acceptable to customers. LNG imports rose 5% year-on-year by volume and 25% by value to $5.6 billion during April-July, according to oil ministry data. August imports rose 5% over July, according to Kpler.

Overall domestic gas consumption has also held up, rising about 0.5% year-on-year to 22.9 billion cubic meters (bcm).

"The resilience in India's LNG imports is being driven primarily by continued growth in city-gas demand and broadly stable fertiliser consumption," said Sonal Ranjan, analyst at analytics firm Kpler. "These are relatively price-insulated parts of India's gas market: city gas benefits from priority domestic gas allocation, while fertiliser is heavily supported through government subsidies."

Demand supported by fertiliser demand, rising CNG use, falling domestic output

The fertiliser sector was the largest driver of imports, accounting for a quarter of total LNG imports in the April-July period. Its imported gas consumption was 5% more than last year, which, at this year's higher prices, would inflate the government's fertiliser subsidy bill. Cutting fertiliser output due to a gas supply disruption is difficult as it's an essential input for farming. The city gas sector surpassed fertiliser as the country's largest gas consumer for the first time this fiscal year. It accounted for 30% of gas consumption, ahead of fertiliser's 28%.

Its share in imported LNG, however, was 14%, trailing fertiliser's 25%. Growth in city gas consumption was fuelled primarily by rapid growth in CNG vehicle sales, as rising petrol prices shifted consumer preferences towards CNG, which remain cheaper to run despite price hikes. Industry, meanwhile, has faced a supply squeeze in alternative fuels such as LPG, forcing some consumers to continue using pricey LNG even as higher prices partially weighed on demand.

The recent rise in LNG prices and fall in benchmark LPG prices have, however, created an opportunity in some cases, such as Gujarat's Morbi, for industries with dual-fuel capability to switch back to LPG.

Hindustan Times, Mumbai, 16/09/2026
Page No: 1, Size: 24.55cm × 17.44cm

Saudi issues slew of alerts as Houthis step up attacks

Reuters
letters@hindustantimes.com

RIYADH/DUBAI: Saudi Arabia issued security alerts over a range of territory on Tuesday, including in the holy city of Mecca and second-largest city Jeddah, following a week of attacks from Iran-aligned fighters that have drawn it deeper into the Middle East war.

The alerts were swiftly lifted and Saudi authorities did not immediately report whether any incoming projectiles had landed, nor was there any immediate claim of responsibility for attacks.

But the alerts were the widest ranging since an escalation in the conflict last week, and the alarm in Mecca was the first of the war in the city, which houses shrines sacred to all Muslims.

The Iran-aligned Houthis in Yemen have announced a number of major attacks on Saudi Arabia over the past week, including strikes on an air base on Monday they said were in retaliation for airstrikes on Yemen.

Saudi Arabia has blamed a separate pro-Iranian movement, based in Iraq, for an attack on Friday that knocked out one of the Kingdom's most important oil transport routes, the East-West Pipeline across the Arabian desert.

continued on →8

Oil tankers earn $1mn a day as war sparks ship shortage

The cost of hiring an oil tanker on the industry's benchmark trade route topped $1 million a day for the first time, as the Iran war leaves too few ships willing to cross the Strait of Hormuz to collect cargoes.

Vessels hauling oil from inside the Persian Gulf to China were being hired at $1.035 million a day, according to data from the Baltic Exchange in London on Monday. The benchmark route has become less relevant during the war because the main means of exporting Persian Gulf oil has shifted to shuttling barrels through Hormuz for collection just outside by tankers that don't want to navigate the strait. BLOOMBERG

WEST ASIA CONFLICT

Crude oil should be flowing through the pipeline within days, U.S. Energy Secretary Chris Wright told CNBC on Tuesday.

A Saudi-led military coalition fighting against the Houthis in Yemen said 13 civilians had been wounded in the Houthis' attacks on Saudi Arabia on Monday. The Iran-backed fighters launched a lightning advance along Yemen's western coast last week, culminating in the seizure of an island in the mouth of the Red Sea.

The escalation in a new theatre in the Middle East conflict has strengthened Iran's hand in its war with the U.S. and further jeopardised global oil supplies.

Officials from a Saudi-backed Yemeni government, which is based in the south of the country and opposes the Houthis, said the Saudi and Yemeni air forces had been responding to Houthi advances by stepping up aerial bombardment of Houthi targets. That included strikes near the historic Red Sea port of Mocha, which the fighters captured last week.

But the Yemeni officials acknowledged that the Houthis had now taken effective control over almost the entire western coast of the country along the Red Sea. "The Houthis are being put under heavy pressure. They in turn are putting more and more pressure on the Saudis, increasing their campaign of missile and drone attacks," one of the Yemeni officials said.

Saudi Arabia's 1,200-km (745-mile) East-West Pipeline, which links its Gulf oil fields to the Red Sea, has been the Kingdom's principal export route while shipping through the Strait of Hormuz has been disrupted by six months of war.

Since the pipeline was shut after Friday's attack, traders say a prolonged closure could cut off as much as 4% of global oil supply. Riyadh has not said when operations might resume, but Wright said on the sidelines of a G20 energy meeting in Houston that he thought "it will be measured in days."

He said Saudi Arabia was taking steps to move more oil out of the Strait of Hormuz with assistance from the U.S. military. The new Houthi presence in the Bab el-Mandeb, or "Gate of Tears", the strait at the mouth of the Red Sea, could further jeopardise that crucial export route.

Mint, Delhi, 16/09/2026
Page No: 8, Size: 40.75cm × 63.50cm

Oil executives say the great fuel crisis is here

Chevron's Mike Wirth, others warn global supplies are running low, with no respite in sight

Benoît Morenne & Collin Eaton

Chevron Chief Executive Mike Wirth. REUTERS

American oil executives warned for months that the prolonged closure of the Strait of Hormuz was bound to cause a fuel crisis. Now, they say it is here.

Commercial fuel stocks around the world have been depleting for more than six months, and strategic crude reserves can't be tapped much further. Attacks last week shut down a crucial crude pipeline in Saudi Arabia that bypassed the Strait, stranding at least 2.5 million barrels a day from an already tight global oil market, analysts estimate.

"All these mechanisms helped to mitigate the price and supply risk," Chevron Chief Executive Mike Wirth said Friday at an energy conference in Austin, Texas. "Those have largely now played out, and we don't have nearly the buffers in the system that we did when it began."

It is hard to predict where oil prices will go, he added, but at the moment, it is difficult to envision prices coming back down quickly. "I wish I could tell you that I saw some reason why things would ease, but it's difficult right now to see that happen," he said.

Veteran energy advisers say that with no resolution to the Iran war in sight, the situation risks spinning out of control. Diesel prices have soared to a record $6.23 a gallon and gasoline prices, which slipped below $4 a gallon this summer, have rebounded to $4.32. Some energy analysts say they have been fielding investor questions about when consumers pinched by the high prices will start pulling back on new purchases.

The Trump administration has repeatedly promised Americans that prices at the pump would decline and that energy flows out of the Middle East would keep increasing.

Interior Secretary Doug Burgum said at a Houston G-20 event on Monday that "the prices in the prior administration were this high anyway" and that Americans would have paid those prices permanently because former President Joe Biden was "pursuing a policy of energy subtraction and shutting down refineries."

"If you want to write about the prices, make sure you include the word 'temporary' because this is a temporary disruption," Burgum told reporters.

The White House sees two big levers it can pull to help ease prices: boosting production in Venezuela and increasing U.S. fuel-making capacity. In recent months, U.S. officials have focused on striking deals that are expected to bolster Venezuela's oil production. In early September, they met with U.S. refining executives to discuss raising the nation's fuel-making capacity. They are pleased with progress thus far on both fronts, a senior U.S. official said.

Energy executives and White House officials say they have had a continuing dialogue about the energy situation since the conflict broke out, and CEOs including Wirth talk to Energy Secretary Chris Wright frequently.

But Wirth said Friday that he hadn't talked to President Trump since Aug. 3, when the president said in a Truth Social Post that the CEO hadn't credited his administration for the oil industry's good fortunes. Trump called on Chevron and oil companies to bring "consumer (retail!) Oil Prices DOWN, NOW!"

THE WALL STREET JOURNAL.

Some CEOs and energy advisers say they have grown alarmed in recent weeks as the conflict has picked back up, with ships and energy infrastructure being targeted in both directions.

"The advantage in most negotiations usually goes to the side that has time on their side, and is willing to be patient," said Wil VanLoh, founder and CEO of Quantum Capital Group, during the Austin conference. Iran, he said, "is willing to suffer. Their people have already suffered a lot for many decades."

China is in part helping to fuel the global supply pinch. The world's largest oil importer for months had relied on its own stockpiles of crude for nearly half of its daily consumption, providing a reprieve for oil markets. But in recent weeks, it has resumed bigger purchases from international suppliers, analysts said.

U.S. crude prices have jumped 19% in the past three weeks to trade near $101 a barrel as attacks in the Middle East multiply. Iran has targeted oil tankers traversing the Strait, even after Trump and his lieutenants boasted about escorting several vessels undetected through the waterway. Houthi militants have recently launched attacks from Yemen on Saudi Arabia's infrastructure and military sites and damaged the East-West pipeline that stretched from the Abqaiq oil field to Yanbu al-Bahr, a major Saudi port city, on the Red Sea.

Commercial fuel stocks have been depleting for over six months, and strategic crude reserves can't be tapped much

Trump has vowed to impose economic pressure on Iran and ruled out sending boots on the ground. He has said he expects the war will last until the November midterm elections, but investors say they believe the war will go well beyond that.

"That was the signal this is going to stretch on," said Dan Pickering , founder of Pickering Energy Partners, a financial firm.

Meanwhile, he said, diesel supplies are tight because of refinery outages following conflicts in the Middle East and Russia. Demand for the fuel is expected to increase as farmers that use it for heavy equipment enter harvest season. "Diesel has no easy solution," Pickering said.

Trump has said Ukraine must halt strikes on Russia that endanger global supplies of diesel.

In March, the CEOs of the three largest U.S. oil companies, ExxonMobil, Chevron and ConocoPhillips, warned Trump officials, including Burgum and Wright, that a prolonged closure of the Strait could lead to a shortfall in refined products such as diesel, *The Wall Street Journal* reported at the time. Some executives have been privately critical of Trump's handling of the conflict.

At the conference Monday, Burgum rejected persistent speculation that the White House is seriously weighing a temporary ban on U.S. exports of refined products such as diesel. Trump's team, he said, doesn't believe such a move would quell prices.

"We will do anything that helps the price at home," Burgum said. "But we're also going to be smart about it, and not just have some idea that if we stop exporting, that somehow magically is going to help the prices."

©2026 DOW JONES & COMPANY, INC.

feedback@livemint.com

Crude basket near $130 again, fiscal worries return

● Growth, inflation risks rise; CAD likely to widen

SAURAV ANAND
New Delhi, September 15

INDIA'S CRUDE OIL basket has soared nearly 30% in less than two weeks to $128.7 a barrel on September 14 from $99.35 on September 2, a development that could sharply raise the country's import bill, widen the current account deficit and lead to a resurfacing of the fiscal worries that had abated for a few weeks since mid-June.

Costlier crude imports could also stoke inflation at a time when it has started to rise again on account of higher food prices and the pass-through effect of fuel price increases.

PRICE PRESSURE

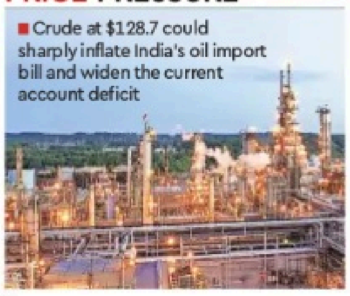

■ Costlier fuel could add 20-25 basis points to inflation, compounding renewed food-price pressures

■ Higher crude and fertiliser input costs could force another upward revision to the fertiliser subsidy bill

Further, fuel marketing margins of state-run oil companies may be pushed deeper into the red again.

"India can absorb crude above $110 a barrel, but at a rising economic cost. Every $10 increase in crude could widen the current account deficit by 0.35-0.5 percentage point of GDP, add 20-25 basis points to inflation and shave 15-20 basis points off GDP growth," an analyst tracking the sector said.

The macroeconomic risks turn sharper if crude remains close to $130.

Continued on Page 11

Crude basket near $130 again

CHIEF ECONOMIC ADVISOR V Anantha Nageswaran told the Standing Committee on Finance on March 2 that crude at $130 a barrel for two-three quarters could pull FY27 growth down to 6.4%, push inflation to 5.5% and widen the CAD to around 3.2% of GDP.

The fiscal impact could be felt more in the form of a spike in fertiliser subsidies. As against the budget estimate of ₹1.77 lakh crore, the subsidy on soil nutrients was seen to rise to around ₹3 lakh crore given the elevated prices of crude oil and its derivatives, LNG and imported fertilisers that prevailed in March-April. The estimates have since been revised to ₹2.2-2.3 lakh crore, but the latest volatility in crude prices could necessitate another upward revision of the estimate.

The basket had climbed to $115.98 a barrel on September 9 before rising another 11% in five days. Its September now at $109.76 a barrel, nearly 22% higher than $90.19 in August. The basket averaged $82.04 in July, $83.22 in June, $106.23 in May and $114.48 in April.

"If crude remains at $110-115 a barrel for six months, the import bill could increase by $56-64 billion, growth could slip below 6% and inflation could remain above 5%," the analyst said. India has around 74 days of total fuel reserves, limiting the immediate risk of physical shortages and making the impact largely financial, the analyst added.

Prashant Vasisht, senior VP and co-group head, corporate ratings, ICRA, said the Indian crude basket was around $128-129 a barrel on September 14, with prices rising due to the twin impact of renewed hostilities around the Strait of Hormuz and the closure of the Saudi East-West pipeline.

The crude spike has already hit oil marketing companies. Vasisht said marketing margins adjusted for Special Additional Excise Duty (SAED) are currently negative ₹7.7 a litre on petrol and ₹2.6 a litre on diesel. Without the SAED adjustment, margins are negative ₹9.2 a litre on petrol and ₹27.6 a litre on diesel.

"If pump prices are not revised and this scenario continues, under-recoveries on domestic LPG and auto fuels could be substantial," Vasisht said. Total under-recoveries for OMCs were already around ₹61,900 crore at the end of the June quarter, he added.

Global crude prices remained firm on Tuesday as attacks on Saudi Arabian energy infrastructure kept the kingdom's East-West Pipeline offline, raising concerns that damage to energy assets and transport routes could take longer to repair.

Brent crude futures were 21 cents, or 0.2%, higher at $105.89 a barrel by 1148 GMT.

Supply concerns intensified after Iran-backed Houthi forces in Yemen launched fresh attacks on Saudi Arabia on Monday, while Gulf Arab states postponed planned discussions with Iran.

The disruption is being compounded by higher shipping costs. In the week to September 6, the key Aframax tanker rate for moving crude from Russia's Black Sea port of Novorossiysk to West India rose for a seventh consecutive week, increasing 2.7% from the previous week. Freight to India has climbed to $23.20 a barrel, while the corresponding cost to North China is $25.70 a barrel.

Sumit Ritolia, lead analyst for refining supply and modelling at Kpler, said: "The closure of the Saudi East-West Pipeline further reduces routing flexibility for Indian refiners at a time when several key oil transit routes are already under pressure."

"India will likely lean even more on diversification across Russia, the US, West Africa, Latin America and other non-Middle East sources to reduce exposure to any single corridor. Russian crude remains particularly important. With multiple chokepoints facing disruption, Russian barrels routed through the Black Sea and Baltic become more valuable from a supply-security perspective," he said.

Virat Vaibhav, Delhi, 16/09/2026
Page No: 10, Size: 28.23cm × 15.40cm

जिला पूर्ति अधिकारी ने पंप संचालकों को दिए कड़े निर्देश, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

एक अक्टूबर से बिना पीयूसीसी पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

वैभव न्यूज ■ गाजियाबाद

जिले में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। एक अक्टूबर से गाजियाबाद में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नीति लागू होने जा रही है। इसके बाद जिस वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नीति को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट कर दिया है कि एक अक्टूबर के बाद बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहन में

ईंधन डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमित तिवारी ने अधिकारियों और पेट्रोल पंप कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि नीति लागू होने के बाद जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने कहा कि जिले में एक अक्टूबर से 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नीति हर हाल में लागू की जाएगी। नीति लागू होने में अभी करीब 15 दिन का समय है और इस अवधि में सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पंप संचालकों से कहा कि वे समय रहते एएनपीआर कैमरे समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर लें, ताकि एक अक्टूबर से व्यवस्था लागू करने में किसी प्रकार की समस्या न आए। उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की है कि यदि उनके वाहन का पीयूसीसी प्रमाणपत्र नहीं बना है या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है तो वे तत्काल नया प्रमाणपत्र बनवा लें। ऐसा नहीं करने पर एक अक्टूबर के बाद पेट्रोल और डीजल लेने में परेशानी हो सकती है।

प्रशासन का मानना है कि पीयूसीसी के बिना चल रहे वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण से प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलेगी। अब आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरों की स्थापना और व्यवस्था की तैयारियों की निगरानी के साथ ही नियमों के पालन को लेकर जिला पूर्ति विभाग की सख्ती और बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को सितंबर माह के भीतर एएनपीआर कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैमरों की मदद से पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहन के नंबर की पहचान कर यह पता लगाया जा सकेगा कि उसके पास वैध पीयूसीसी है या नहीं। यदि वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नहीं होगा तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। जिन पेट्रोल पंपों पर निर्धारित समय तक एएनपीआर कैमरे नहीं लग पाते हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वाहन में ईंधन डालने से पहले सेल्समैन वाहन स्वामी से पीयूसीसी प्रमाणपत्र दिखाने को कहेगा।

संकटः हूतियों के हमले से तेल आपूर्ति लड़खड़ाने लगी

सना, एजेंसी। हूती विद्रोहियों के हमले के कारण सऊदी अरब की अहम ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसकी वैश्विक तेल आपूर्ति में 4 से 5% की हिस्सेदारी है। इस कारण मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) की कीमत 1.24 डॉलर बढ़कर 106.93 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

हालिया घटनाक्रम से हूती विद्रोहियों एवं सऊदी के बीच तनाव और बढ़ गया है। सऊदी ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह उसके हमलों का मजबूती से जवाब देगा। वहीं, पश्चिमी यमन में हूतियों के हमले में सरकारी सेना के आठ सैनिक मारे गए। एक हूती अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यमन पर हवाई हमले किए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, इनमें दो बच्चे शामिल हैं। हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हाजेम अल-असद ने जवाबी हमले तेज करने का दावा किया। › मक्का में चेतावनी P17

पोत परिवहन और क्षेत्रीय सुरक्षा को खतराः भारत

नई दिल्ली। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचना और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर मंगलवार को चिंता जताई। आगाह किया कि ऐसे हमले क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करते हैं और बाब-अल-मंदेब से पोत की आवाजाही के लिए खतरा पैदा करते हैं।

मक्का, ताइफ और जेद्दा में हमले की चेतावनी

सना, एजेंसी। सऊदी सिविल डिफेंस ने मंगलवार को मक्का में संभावित खतरे की चेतावनी जारी की। यमन के हूतियों के साथ तनाव बढ़ने के दौरान ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कहा कि खतरा टल गया। इन संक्षिप्त चेतावनियों में ताइफ और जेद्दा प्रांत भी शामिल थे। वहीं, सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा विभाग ने छह क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की। बाद में इन चेतावनियों को हटा लिया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसद और अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी वेस्ली हंट को सऊदी अरब में अमेरिका का नया राजदूत बनाने के लिए नामित किया। ईरान के साथ युद्ध के बीच यह राजदूत का पद काफी समय से खाली था।

सऊदी पाइपलाइन से भारत पर कितना पड़ेगा असर

1 क्या इस बंदी से भारत में तेल की सीधी कमी या आपूर्ति संकट पैदा होगा?

हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद 10 सितंबर को सऊदी की 1200 किमी लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद किया गया था। इससे भारत को कच्चे तेल की भौतिक आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। भारत सऊदी तेल पर सीमित रूप से ही निर्भर है। अगस्त में भारत के कुल 47 लाख बैरल प्रतिदिन के कच्चे तेल आयात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी केवल 315000 बैरल प्रतिदिन थी।

2 यदि आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी तो भारत के लिए चिंता की बात क्या है?

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल का आयात बिल बढ़ना है। पाइपलाइन बंद रहने से एशियाई देशों को अमेरिका, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से वैकल्पिक तेल खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। इससे कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी।

3 वैश्विक बाजार में कीमतों और भारतीय तेल रिफाइनरियों पर इसका क्या असर होगा?

वर्तमान में ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है और अन्य तेल ग्रेड भी महंगे हो चुके हैं। भारतीय तेल रिफाइनरियों के लिए इसका मिला-जुला असर रहेगा। ईंधन के दाम बढ़ने से रिफाइनरी मुनाफा बढ़ सकता है पर कच्चे तेल की अधिक लागत इस लाभ को कम कर सकती है।

4 यदि पाइपलाइन की मरम्मत में देरी हुई तो स्थिति कितनी गंभीर होगी

लाल सागर तट पर मौजूद तेल का भंडार केवल 7 से 10 दिनों की स्थानीय जरूरतों और निर्यात को पूरा कर सकता है। अगर मरम्मत में इससे अधिक समय लगता है तो रिफाइनरियों को उत्पादन घटाना पड़ेगा। जिससे वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत और कीमतें दोनों बढ़ सकती हैं।

Loksatya, Delhi, 16/09/2026
Page No: 6, Size: 37.47cm × 28.36cm

तेल के रास्ते बंद, सऊदी बेबस, ईरान के हाथ में दुनिया की नब्ज

अजय कुमार

महंगा तेल अमेरिका के लिए आर्थिक ही नहीं, घरेलू राजनीतिक संकट भी बन सकता है। यहीं ईरान की परोक्ष युद्ध रणनीति का महत्व समझना होगा। ईरान पर सीधे हमला करना एक बात है, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में मौजूद सशस्त्र गुटों के जरिए ऊर्जा ढांचे को दबाव में लाना दूसरी। इससे जवाबदेही धुंधली रहती है और विरोधी को एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ते हैं। यही वजह है कि किसी हमले की जिम्मेदारी सामने न आने के बावजूद उसके रणनीतिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अब। सऊदी अरब के लिए खतरा अब केवल सीमा पार से आने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि किसी भी दिशा से आने वाला छोटा ड्रोन भी है।अगर पाइपलाइन ही निशाना बन जाए, तो होर्मुज का विकल्प मौजूद होकर भी कमजोर पड़ जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा किसी सैन्य अड्डे जैसी नहीं की जा सकती।

मध्यपूर्व की इस जंग में अब असली निशाना सिर्फ जमीन, बंदरगाह या सैन्य अड्डे नहीं हैं। असली निशाना तेल के रास्ते हैं। सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमले ने दुनिया को फिर याद दिला दिया है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था कितनी नाजुक है। करीब 1200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है और इसकी अधिकतम क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। हमले के बाद इसका संचालन रोकना पड़ा।यही इस हमले का सबसे बड़ा अर्थ है। सऊदी अरब ने ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन इसलिए बनाई थी कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भरता कम हो। सामान्य परिस्थितियों में होर्मुज से प्रतिदिन करीब दो करोड़ बैरल तेल और तेल उत्पाद गुजरते हैं। अब जब होर्मुज युद्ध के कारण दबाव में है और सऊदी का वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग भी चोटिल हो गया, तो बाजार में डर लौटना स्वाभाविक है।कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर के पार जाना इसी डर की कीमत है। ब्रेंट 109 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। बाजार में भविष्य की कमी की आशंका आज की कीमत बढ़ाती है। यदि पाइपलाइन लंबे समय तक बंद रहती है, तो यानबू से निर्यात प्रभावित होगा और सऊदी अरब को आपूर्ति की नई गणित बनानी पड़ेगी। जिस पाइपलाइन से हाल में लगभग 40 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल गुजर रहा था, उसका रुकना वैश्विक बाजार के लिए बड़ा झटका है। यह वैश्विक आपूर्ति का लगभग चार प्रतिशत हिस्सा है।सऊदी अरब की मुश्किल यह है कि उसके सामने सिर्फ एक रास्ते का संकट नहीं है। पूर्व में होर्मुज है, दक्षिण में बाब अल-मंदब है और पश्चिम में लाल सागर। हूती हमलों ने बाब अल-मंदब और लाल सागर की जहाजरानी को जोखिम में डाल रखा है। होर्मुज में ईरान के साथ टकराव ने दूसरा बड़ा रास्ता असुरक्षित कर

दिया। अब वह पाइपलाइन भी बंद है जिसे इन्हीं समुद्री जोखिमों का विकल्प माना जाता था।

इस घटना को सिर्फ सऊदी अरब पर हमला मानना भूल होगी। तेल की कीमत केवल उत्पादन से तय नहीं होती; परिवहन, बीमा, भंडार और जोखिम भी उसकी कीमत बनाते हैं। पाइपलाइन बंद होने का मतलब यह नहीं कि दुनिया से अचानक लाखों बैरल तेल गायब हो गया। मतलब यह है कि उपलब्ध तेल को बाजार तक पहुंचाना कठिन और महंगा हो गया।भारत के लिए असली चिंता यहीं से शुरू होती है। घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की हर छलांग को उसी दिन नहीं दिखातीं। तेल कंपनियां पुराने स्टॉक और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर झटका कुछ समय रोक सकती हैं। लेकिन यदि कच्चा तेल लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर रहता है, तो दबाव बढ़ेगा। भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपये पर दबाव आएगा और महंगे परिवहन का असर खाद्य पदार्थों से लेकर उद्योग तक दिखाई देगा।इस संकट का राजनीतिक चेहरा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का रक्षा समझौता किया है। यदि सऊदी के तेल ढांचे पर लगातार हमले होते हैं, तो सवाल उठेगा कि सुरक्षा साझेदारी केवल राजनीतिक बयान है या जरूरत पड़ने पर सैनिक, हथियार और वायु रक्षा भी सामने आएगी।आज सऊदी अरब और हूती एक-दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1934 में सऊदी-यमन युद्ध के बाद असीर और नजरान जैसे इलाके सऊदी नियंत्रण में आए। फिर 1962 में यमन की राजशाही गिरने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने गणतांत्रिक सरकार के समर्थन में सेना भेजी। एक समय यमन में लगभग 70 हजार मिस्री सैनिक मौजूद थे। सऊदी अरब ने जवाब में जैदी राजशाही समर्थकों को पैसा, हथियार और मदद दी। जिन जैदी परंपराओं से आगे चलकर हूती आंदोलन निकला, उनके पूर्ववर्तियों को कभी सऊदी समर्थन मिला था।आधुनिक हूती आंदोलन ने बाद में सऊदी और यमनी सत्ता दोनों के लिए चुनौती पैदा की। 2004 से 2009 के बीच कई युद्ध हुए और 2009 में सऊदी सेना सीधे संघर्ष में उतरी। पहाड़ी भूगोल और गुरिल्ला युद्ध ने सऊदी सेना को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। 2019 में हूतियों के हमले ने इसी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया था।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की रणनीति क्या है। यदि होर्मुज को दबाव में रखकर और उसके समर्थक गुटों के जरिए लाल सागर तथा तेल ढांचे पर खतरा बढ़ाकर वह अमेरिका और उसके सहयोगियों की आर्थिक लागत बढ़ाता है, तो युद्ध का मैदान मिसाइलों से निकलकर वैश्विक बाजार में पहुंच जाता है। महंगा तेल अमेरिका के लिए आर्थिक ही नहीं, घरेलू राजनीतिक संकट भी बन सकता है। यहीं ईरान की परोक्ष युद्ध रणनीति का महत्व समझना होगा। ईरान पर सीधे हमला करना एक बात है, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में मौजूद सशस्त्र गुटों के जरिए ऊर्जा ढांचे को दबाव में लाना दूसरी। इससे जवाबदेही धुंधली रहती है और विरोधी को एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ते हैं। यही वजह है कि किसी हमले की जिम्मेदारी सामने न आने के बावजूद उसके रणनीतिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अब। सऊदी अरब के लिए खतरा अब केवल सीमा पार से आने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि किसी भी दिशा से आने वाला छोटा ड्रोन भी है।अगर पाइपलाइन ही निशाना बन जाए, तो होर्मुज का विकल्प मौजूद होकर भी कमजोर पड़ जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा किसी सैन्य अड्डे जैसी नहीं की जा सकती। हर किलोमीटर पर सैनिक तैनात करना संभव नहीं। यही इस हमले की असली रणनीतिक ताकत है एक छोटा ड्रोन हजारों किलोमीटर की ऊर्जा रणनीति को अस्थायी रूप से पंगु बना सकता है।आने वाले दिनों में निर्णायक बात यह होगी कि सऊदी अरब पाइपलाइन कितनी जल्दी बहाल करता है और लाल सागर तथा होर्मुज की स्थिति कितनी सुधरती है। अगर एक रास्ता बंद, दूसरा असुरक्षित और तीसरा हमले की जद में रहा, तो 120 डॉलर का तेल भी असंभव नहीं होगा। तब संकट केवल पेट्रोल-डीजल की कीमत का नहीं रहेगा। आयात बिल, महंगाई, मुद्रा और वैश्विक विकास सभी पर असर पड़ेगा। सौ बात की एक बात यही है मध्यपूर्व की जंग अब सीमाओं के भीतर नहीं रही। उसकी असली लपटें तेल के रास्तों तक पहुंच चुकी हैं।

Loksatya, Delhi, 16/09/2026
Page No: 9, Size: 31.06cm × 15.77cm

तीन तेल मार्ग बाधित, दुनिया पर मंडराया संकट

- **यहोर्मुज-बाब अल मंदेब के बाद सऊदी की पाइपलाइन भी ठप, कच्चे तेल में लगी आग; भारत समेत आयातक देशों पर बढ़ा खतरा**
- **वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 4% प्रभावित होने का अनुमान, सऊदी के यानबू में महज 5-7 दिन का निर्यात स्टॉक बचा**

नई दिल्ली, लोकसत्य। दुनिया एक बार फिर बड़े तेल संकट की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल जरूरत पूरी करने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य पहले से बाधित है।

इसके बाद लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब पर हूती हमलों ने तेल परिवहन को प्रभावित किया है। अब सऊदी अरब की करीब 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन भी ड्रोन हमलों के कारण बंद हो गई है। तेल के इन तीन प्रमुख समुद्री और वैकल्पिक रास्तों में रुकावट ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। उसकी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन आपात स्थिति में तेल को फारस की खाड़ी से हटाकर लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है। इसकी क्षमता करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन बताई जाती है। इसके बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ सकता है।रिपोर्टों के

मुताबिक यानबू के पास सऊदी अरब के अनुमानित 3.5 करोड़ बैरल तेल भंडार में अब केवल पांच से सात दिनों का निर्यात स्टॉक बचा है। मिस्र के ऐन सुखना और सिदी केरीर बंदरगाहों पर अतिरिक्त भंडार से कुछ और दिनों का सहारा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने पर संकट गहरा सकता है।आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अगस्त में सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन घटकर करीब 62.40 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जिसे 1990 के बाद का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। इससे पहले जुलाई के मुकाबले उत्पादन में करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट दर्ज होने की बात सामने आई थी।इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड करीब 109 डॉलर, डब्ल्यूटीआई करीब 103 डॉलर और मुर्बान क्रूड लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी तेजी देखी गई।यदि तीनों मार्गों पर लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है तो पेट्रोल-डीजल, विमान ईंधन और परिवहन लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह चुनौती और गंभीर हो सकती है। वैश्विक तेल आपूर्ति में संभावित बड़ी कमी के बीच रणनीतिक भंडार भी दबाव में आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में तेल की कीमतों का हर उछाल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नई चिंता बन सकता है।